REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514
VOLUME - 8 | ISSUE - 9 | JUNE - 2019

" डिजिटल इंडिया अभियान का सरकारी प्रयास, लाभ एवं चुनौतियों का एक आलोचनात्मक अध्ययन "

डॉ. कन्हैया कुमार विश्वकर्मा[1] , राजेन्द्र प्रसाद पटेल[2]
[1]अतिथि विद्वान (वाणिज्य) , शास.महाविद्यालय बरही (म.प्र.) भारत.
[2]अतिथि विद्वान (अर्थशास्त्र) , शास.महाविद्यालय उमरिया (म.प्र.) भारत.

प्रस्तावना एवं शोध सारांश :–

भारत सरकार की सकारात्मक पहल एवं अतिरिक्त प्रयास के कारण डिजिटल इंडिया कार्यक्रम व्यापक सफलता का अपना लक्ष्य हासिल करने वाला है। इस कार्यक्रम में आम जनता ने भी अपनी भागीदारी बढाई है और इस प्रकार दुनियाँ के सर्वाधिक डिजिटली सशक्त समाज बनाने में भारत को कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकार और देश के नागरिक एकजुट होकर कई लक्ष्य हासिल कर सकते है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम देश को आने वाले समय और डिजिटल तौर पर विकसित राष्ट्र बना सकेगा।

शब्दकुंजी (Keywords) – डिजिटल इंडिया, ब्लौकम्पनी, बीपीओ, इ–गवर्नेंस,सामान्तर अर्थव्यवस्था, इ–क्रांति, भीमऐप, स्टार्टअप, स्पेकार्ड।

भारत में डिजिटल इंडिया अभियान के तहत डिजिटल पहचान मुहैया कराने डिजिटल आधारभूत संरचना तैयार करने, सेवाओं की डिजिटल उपलब्धता, सुनिश्चित करने और रोजगार व उधम संबंधी अवसर को बढ़ावा देने जैसे विभिन्न उपाय किए गए हैं। इन उपायों ने भारत को डिजिटल सम्पन्न समाज में बदल दिया है और आम नागरिकों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। डिजिटल पहचान मुहैया कराने के लिए देश के तकरीबन 122 करोड़ लोगों को आधार से जोड़ा गया है। इसने सामाजिक कल्याण की विभिन्न योजनाओं की डिलीवरी और सुवाह्यता के लिए लोगों की वास्तविक पहचान के पूरक के तौर पर डिजिटल पहचान मुहैया कराया है।

सरकारी कामकाज के बदलते स्वरूप के साथ अतिरिक्त हितधारकों तथा इ–गवर्नेंस के जानकारों को लगातार नए कौशल और ज्ञान से लैश करना जरूरी है। ऐसा करने पर ही डिजिटल तौर पर सशक्त भारत के लिए प्रभावी रूप से अपना योगदान दे सकेगा। निरंतर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए तकनीक का इस्तेमाल इस तरह से करना आवश्यक है कि शिक्षा और ज्ञान का आदान–प्रदान बिना किसी बाहरी हस्ताक्षेप के एक समान बात बन जाये। 2015 में सरकार द्वारा शुरू किये गये डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उददेश्य भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और डिजिटल तरीके सशक्त समाज के रूप में विकसित करना था। पारदर्शिता, समावेशन,उत्पादकता और कार्य कुशलता को बढ़ाकर किए जा रहे इस परिवर्तनकारी विकास का अन्तर्निहित आधार टेक्नॉलाजी है। डिजिटल इंड़िया के तहत की जा रही पहल और इसके साथ ही टेक्नॉलाजी में हो रहे विकास ने भारत को व्यापक संभावनाओं वाला क्षेत्र बना दिया है जहॉ आशा और प्रतिभा डिजिटल तरीके से अवसरों को पूरा करते हैं। भारत दुनिया के उन शीर्ष देशों में है जिन्होंने टेक्नालॉजी और नवाचार का प्रभावी उपयोग करते हुए

राज–व्यवस्था दृष्टिकोण को सरकार केन्द्रित से नागरिक केन्द्रित बना दिया है, जहाँ इ–सेवाओं के जरिए ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया है जिसमें सहभागितापूर्ण शासन व्यवस्था में नागरिकों का सशक्तिकरण हो और उन्हें निर्णय लेने तथा सरकारी नीतियाँ, कार्यक्रम और कायदे कानून बनाने के कार्य में भागीदारी बनाया जा सके। अपनी इस डिजिटल आधारभूत ढ़ाचे और विस्तारित डिजिटल पहुच की मजबूत नींव रखने के बाद अब भारत विकास के अगले चरण में पहुचने की तैयारी कर रहा है, जिसमें जबरदस्त आर्थिक लागत का सृजन होगा। यही नहीं, जैसे–जेसे एक क्षेत्र के बाद दूसरे क्षेत्र में नए डिजिटल अनुपयोग का उपयोग शुरू हो रहा है, करोड़ों भारतीयों का सशक्तिकरण हो रहा है।

शोध के उददेश्य (Objectives) – शोध के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :–

1. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को सशक्त बनाने हेतु सरकारी प्रयास का अध्ययन
2. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से प्राप्त हो रहे भारत के लाभों का अध्ययन

शोध प्रविधि (Research Methodology) :–

यह शोध द्वितीयक समंकों पर आधारित है। अवधारणा की व्याख्या के लिए द्वितीयक समंक विभिन्न पत्र, पत्रिकाओं एवं किताबों आदि से संग्रहित किए गए है। इसमें परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों तरह के तथ्यों का प्रयोग किया गया है। वर्ष 2014 एवं 2018 के मध्य हुए डिजिटल क्रान्ति से लाभ का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

डिजिटल इंडिया का सशक्त बनाने हेतु सरकारी प्रयास :–

देश की ढ़ाई लाख ग्राम पंचायतों को नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) के जरिए जोड़ने की योजना है। इस योजना को तार्किक परिणाम तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने 1000 करोड़ रू. की अधिकृत पूंजी से भारत ब्रांड बैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) की स्थापना की है। इस योजना से पंचायतों के सभी नागरिक व्यापक तौर पर लाभांवित होगें।

पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम के अंतर्गत सरकार की योजना ढ़ाई लाख कॉमन सर्विस सेन्टर (सीएससी) खोलने की है अर्थात् हर ग्राम पंचायत में एक सीएससी खोली जायेगी। भारत में करीब 1.62 लाख ग्राम पंचायतों में दो लाख 42 हजार सीएससी है। ये केन्द्र सरकारी एवं कारोवारी सेवाओं की डेलवरी के लिए अंतिम बिन्दु होगें।

ई–क्रांति के तहत 44 मिशन मोड प्रोजेक्ट निष्पादित किए गए है, आज, ई–क्रांति के माध्यम से 3325 ई–सेवाएं चलायी जा रहीं है, जो इसकी आपार सफलता का परिचायक है।

भारतीय बीपीओ संवर्धन योजना के अंतर्गत देशभर में 48300 बीपीओ, आईटीईएस केंद्र स्थापित करने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कुल 493 करोड़ रू. के परियोजन व्यय वाली इस योजना से बुनियादी ढ़ाचा एवं मानव श्रम की ष्टि से छोटे शहरों एवं गावों में छमता निर्माण में मदद मिलेगी।

लोगों को उनकी डिजिटल यात्रा पर निरंतर अग्रसर करते रहने के लिए यूनिफाइड मोबाइल एटिलकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेस(उमंग) शुरू किया गया है। यह मोबाइल एप अकेले ही 307 से अधिक सरकारी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराता है और इसके तहत 1200 से अधिक डिजिटल सेवाएं इकट्ठा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। नवम्बर 2017 के विमोचन के बाद से 84 लाख अधिक से उपभोक्ताओं ने इसे डाउनलोड़ किया है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण साक्षरता अधिनियम के तहत देश के 6 करोड़ लोगों को साक्षर बनाना है। 1 करोड़ 23 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

डिजिटल इंडिया मिशन से भारत को लाभ :–

- देश में डिजिटल लेन–देन में कई गुना बढ़ोतरी हुई है और भुगतान में डिजिटल तरीका अपनाने में भारत कई पायदान ऊपर चढ़ गया है। जहां 2014–15 में 335 करोड़ डिजिटल लेनदेन हुए थे, वहीं 2017–18 में इसकी संख्या 2070.98 करोड़ तक पहुंच गई।
- ऑनलाइन पंजीयन प्रणाली से अस्पतालों में लगने वाली लंबी–लंबी कतारें कम हो गई है और स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली कायम हो गई है। देश के 318 अस्पतालों को ई–हॉस्पिटल से जोड़ दिया गया है और 5.6 करोड़ ई–हॉस्पिटल लेनदेन इसके माध्यम से किए जा चुके हैं।

- आज भारतीय स्टार्टअप जबरदस्त बदलाव से उत्पन्न व्यापक संभावनाओं का फायदा उठाने के लिए तरक्की कर रहे हैं। 2018 में 1200 से अधिक स्टार्टअप गठित किए गए। इस तरह देश में स्टार्टअप की कुल संख्या 7200 जा पहुंची है। मोबाइल टेलीफोन का उत्पादन भी कई गुना बढ़ गया है। 2014 में देश में मोबाइल फोन पर आने वाली केवल दो इकाइयां थी और आज 127 इकाइयां मोबाइल हैंडसेट और इनके हिस्से पुर्जो का उत्पादन कर रही है। इससे रोजगार के 4.5 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवसर उपलब्ध हुए है।
- सरकार द्वारा कराए गए एक अध्ययन से पता चला है कि इलेक्ट्रानिक वस्तुओं की मांग में 22ः की सीएजीआर की बढ़ोतरी हुई है और इसके 2020 तक 400 बिलियन डालर तक पहुचने का अनुमान है। इलेक्ट्रानिक निर्माण क्षेत्र में पिछले 2 वर्ष में करीब 1.28 लाख करोड़ रूपये के 50 से अधिक निवेश प्राप्त हुए है।
- भारतीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर नोटबंदी के असर के बारे में बताते हुए कहा है ि कइस अवधि में प्रत्यक्ष कर में 14.4 फीसदी और सीमा कर में 6 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है।
- वर्ष 2015–16 प्रत्यक्ष लाभ हस्थानांतरण के माध्यम से 30 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 61 हजार करोड़ रूपए से अधिक की धनराशि वितरित की गई है। 1.6 करोड़ फर्जी राशन कार्ड हटाकर 10,000 करोड़ रू. की बचत की गई है।
- भारत आज ऐसे निर्णायक मोड़ पर खड़ा है यह डिजिटल इंडिया की मजबूत नींव रखी जा चुकी है और सूचनाओं तथा सेवाओं तक पहुच आसान हो जाने से भारत को आर्थिक और सामाजिक जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में डिजिटल टेक्नोलॉजी की क्षमता के बेहतर उपयोग से मदद मिली है। इससे भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने की ओर बढ़ रही है और 2025 तक रोजगार के 5.5 से 6 करोड़ अवसरों की संभावना बढ़ गई है।
- भीम एप यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के इस्तेमाल से डिजिटल लेनदेन को सरल, सुगम तथा त्वरित बनाता है। गत वर्ष 30 दिसंबर को लांच होने के बाद से भीम ऐप के इस्तेमाल में कई गुना वृद्धि हुई है। हाल ही में किए गए अध्ययन से पता चला है कि 2 माह में भीम ऐप को एक करोड़ 70 लाख बार डाउनलोड किया गया और फरवरी 2018 अंत तक 19 लाख 37 हजार बार इससे लेनदेन किए गए हैं।

निष्कर्ष :–

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से भारत में डिजिटल क्रांति हुई है। आज संपूर्ण सरकारी योजनाएं डिजिटल की जा रही है ताकि इन तक जनता की पहुंच अधिक सुगम हो सके। डिजिटल तकनीक के माध्यम से योजनाओं का पैसा सीधे हितग्राही के खाते में पहुंच रहा है जिससे भ्रष्टाचार में कमी आई है। जमीन के नक्शा–खसरा आदि रिकार्ड डिजिटल होने के कारण राजस्व विभाग में भी भ्रष्टाचार कम हुआ है। डिजिटल लाइब्रेरी से विद्यार्थियों तक नवीन ज्ञान का संचार हुआ है, जिससे शोध की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। आज सारी प्रतियोगी परीक्षाएं इस डिजिटल तकनीक से हो रही हैं, जिससे पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता बढ़ी है। लेकिन इन सफलताओं के बाद भी कई चुनौतियां भी हैं। अतः हमें डिजिटल साक्षरता का प्रचार–प्रसार करना होगा साथ ही डिजिटल क्राइम को भी कंट्रोल करना पड़ेगा तभी जनता के बीच डिजिटल तकनीक के प्रति विश्वसनीयता में वृद्धि हो सकेगी और यह डिजिटल भारत कार्यक्रम सफल होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. जगन्नाथ कुमार कश्यप, 'ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन और डिजिटल इंडिया' कुरूक्षेत्र, अगस्त 2017
2- स्वदेश सिंह, 'नोटबंदी और डिजिटल लेनदेन से गरीब कल्याण योजना' फरवरी 2017
3- ओंकार राय 'सशक्त डिजिटल समाज बनाता भारत' योजना मई 2017
4- सिम्पी चौधरी, 'डिजिटल इंडिया का परिवर्तनकारी प्रभाव' योजना दिसंबर 2018
5- एस वाई कुरैशी, 'विमुद्रीकरण : चुनाव पर प्रभाव' योजना फरवरी 2017